

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020 (CHAITRA 12, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020

संख्या 32/आ०—1/पं०अ०1/1914/धा० 58/2020.— चूंकि राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि नियम तुरन्त लागू होने चाहिए; इसलिए पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 58 की उप—धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये प्रथम अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
- 2. हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 में, नियम 5 में, उप—नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "(1) इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, प्ररूप अनु0—52 (अनुमत कक्ष) में अनुज्ञप्ति तथा उसमें दी गई शर्ती के अध्यधीन शहरी क्षेत्र और जिला गुरूग्राम के मामले में अपने जोन की लाईसैंस फीस की 3 प्रतिशत की निर्धारित फीस पर अन्य राज्यों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में तथा राज्य के अन्य जिलों के मामले में 1.5 प्रतिशत पर दी जा सकती है। अनुमत कक्ष चारिववारी के बिना खुले स्थान में संचालित नहीं किया जाएगा। स्थान गुप्त तथा बन्द होना चाहिए, स्थान साधारणतः राहगीर के लिए दृश्य नहीं होगा तथा ऐसे स्थान में पहुंच उचित सीमांकित प्रवेश के द्वारा होनी चाहिए। सम्पूर्ण उद्देश्य राहगीर के सम्पूर्ण विचार में लोगों को शराब पीने से रोकना है। अनुमत कक्ष केवल ठेके तथा उसी परिसर में निकटवर्ती स्थान में चलाया जाएगा। अनुमत कक्ष का क्षेत्र अनुमत कक्ष के अनुमोदन के समय पर उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा। मदिरा अनुमत कक्ष में किसी रीति में बेची / परोसी नही जाएगी।

जनता में हुल्लड़बाज (उपद्रवी) तथा पियक्कड़ व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक खुदरा ठेके में एक अनुमत कक्ष सम्बन्धित नगर निगम/परिषद्/समिति की बाहरी सीमा तथा अन्य राज्यों की सीमा (बार्डर) से 5 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले शहरी तथा उप शहरी क्षेत्रों में मदिरा (अनु—14क/अनु—2) के प्रत्येक खुदरा बाजार के लिए आबकारी नीति तथा सम्बन्धित आबकारी नियमों/मादक अनुज्ञप्ति तथा विकय आदेश, 1956 के उपबन्धों के अनुसार सही रूप से उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा। आगे अनुमत कक्ष को उन जगहों पर भी अनुमित दी जा सकती है जहाँ हरियाणा राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर

पार्क मानेसर, टैक्नोलोजी पार्क, पंचकूला, इत्यादि। अनुज्ञप्तिधारी को उचित ढांचा तथा फर्नीचर रखना तथा सफाई तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण बनाए रखना अपेक्षित है। अनुमत कक्ष चलाने वाले लाईसैंसधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति के पास जीएसटीन नम्बर होना चाहिए और एफएसएसएआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए।"।

अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2020

No. 32/X-I/P.A.1/1914/S.58/2020.— Whereas the State Government considers necessary that the rules should be brought into force at once; so in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (2) and (3) of section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2020.
- 2. In the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) Subject to other provisions of these rules, a license in form L-52 (Anumat Kaksh) and subject to the conditions contained therein may be granted in Urban Zone and in the Zones having border areas with the other States at a fixed fee of 3% of license fee of the respective zone in case of district Gurugram and 1.5% in case of the other districts in the State. The Anumat Kaksh shall not be operated in an open space without boundary. The space shall to be confined and enclosed and shall not be a thorough fare or a crossing being used by general public. The space shall not be ordinarily visible to the passersby and the access to such a space should be through a well defined entry. The overall objective is to prevent drinking in public in full view of the passersby. Anumat Kaksh shall only be operated from adjoining place to the vend and in the same premises. The area of Anumat Kaksh shall be approved by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of the Anumat Kaksh and licensee shall not encroach beyond the area approved. Liquor shall not be sold or served in any manner in the Anumat Kaksh.

In order to prevent rowdy and drunken behavior in public, one Anumat Kaksh with each retail vend, shall be allowed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) strictly as per the provisions of the Excise Policy and relevant Excise Rules/Intoxicants License and Sales Orders 1956, for each retail outlet of liquor (L-14A/ L-2) in urban areas and sub-urban areas falling within five Kilometers from the outer limit of respective Municipal Corporation/Council/Committees and borders with other States. Further, Anumat Kaksh may also be allowed in places where Haryana State Infrastructure and Industrial Development Corporation has developed industrial Model Township and theme/specialized parks like IMT Manesar, IMT Bawal, IMT Rohtak, IT Park Manesar, IT Park Panchkula, etc. The licensee is required to have proper structure and furniture and to maintain cleanliness and hygienic environment. The licensee or his authorized person running Anumat Kaksh must have a GSTIN Number and must be registered with FSSAI".

ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.